eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

भारत के लिए अमेरिका–ईरान तनाव के आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ0प्र0, भारत

Received: 20 Jan 2026, Accepted: 25 Jan 2026, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2026

Abstract

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। ये तनाव केवल पश्चिम एशियाई क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके प्रभावों ने ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, सैन्य रणनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है। भारत, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा–आश्रित विशाल राष्ट्र के रूप में, इस तनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। भारत के लिए इस संघर्ष के परिणामों में कच्चे तेल की लागत, ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी–भारतीय रणनीतिक साझेदारी, ईरानी समुदाय और मध्य पूर्व में निवेश एवं व्यापार अवसर शामिल हैं। यह शोधपत्र विस्तार से विश्लेषण करता है कि अमेरिका–ईरान तनाव का भारत के आर्थिक हितों, रणनीतिक विकल्पों और कूटनीति पर क्या असर पड़ा है, और भारत को भविष्य में किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए।

मुख्य शब्द– अमेरिका–ईरान तनाव, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक भागीदारी, कूटनीति, आर्थिक परिणाम, तेल विपणन, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, मध्य पूर्व नीति

Introduction

21वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) वैश्विक शक्ति–संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा दीर्घकालीन तनाव केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं है, बल्कि यह वैश्विक भू–राजनीतिक संरचना को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक बन चुका है। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद से दोनों देशों के संबंध निरंतर टकराव, प्रतिबंधों, सैन्य प्रतिस्पर्धा और परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों से घिरे रहे हैं। 2015 में संपन्न परमाणु समझौता Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ने कुछ समय के लिए तनाव को कम किया, किंतु 2018 में अमेरिका के समझौते से अलग होने और ईरान पर पुनः कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के निर्णय ने क्षेत्रीय अस्थिरता को फिर बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता, समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर प्रश्न, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दबाव जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। भारत, जो विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इस तनाव से सीधे प्रभावित होता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें पश्चिम एशिया की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ईरान लंबे समय तक भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। साथ ही, भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा रणनीतिक संबंध भी गहरे रहे हैं। दूसरी ओर, 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में। इस प्रकार, अमेरिका–ईरान तनाव की स्थिति में भारत एक जटिल कूटनीतिक द्वंद्व का सामना करता है। एक ओर उसे अमेरिका के साथ अपने सामरिक एवं आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ रखना है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा, क्षेत्रीय संपर्क (जैसे चाबहार बंदरगाह परियोजना) और मध्य एशिया तक पहुँच के अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा भी करनी है। इसके अतिरिक्त, यह तनाव वैश्विक तेल मूल्यों में उतार–चढ़ाव के माध्यम से भारत की

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, विनिमय दर तथा समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। यदि क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है तो समुद्री मार्ग विशेषकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, जो भारत के ऊर्जा आयात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतः यह अध्ययन इस प्रश्न का विश्लेषण करता है कि अमेरिका–ईरान तनाव के संदर्भ में भारत की आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। साथ ही, यह शोध भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों और संभावित नीति–रणनीतियों पर भी प्रकाश डालता है, जिससे वह बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अपने राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रक्षा कर सके। इस शोध का उद्देश्य केवल प्रभावों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति की व्यवहारिकता, संतुलन–नीति (Strategic Autonomy) तथा उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना भी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का इतिहास लगभग सात दशकों पुराना है। यह संबंध मित्रता से शत्रुता तक की यात्रा का उदाहरण है, जिसमें सत्ता परिवर्तन, वैचारिक टकराव, ऊर्जा राजनीति, क्षेत्रीय प्रभाव और परमाणु कार्यक्रम जैसे कारक प्रमुख रहे हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक चरण इस तनाव को समझने में सहायक हैं। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री डवींउउंक डवेंकमही को हटाने के लिए अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी और ब्रिटेन की MI6 द्वारा एक गुप्त अभियान चलाया गया। इसका कारण ईरान द्वारा तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण था, जिससे पश्चिमी शक्तियों के आर्थिक हित प्रभावित हुए। इस तख्तापलट के बाद शाह Mohammad Reza Pahlavi की सत्ता मजबूत हुई और ईरान अमेरिका का प्रमुख सहयोगी बन गया। इस अवधि में दोनों देशों के संबंध घनिष्ठ थे, परंतु ईरानी समाज में अमेरिका–विरोधी भावनाएँ धीरे–धीरे पनपने लगीं।

1979 में Ruhollah Khomeini के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई और शाह को अपदस्थ कर दिया गया। नई इस्लामी सरकार ने अमेरिका को "महान शैतान" कहा और पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया। इसी वर्ष तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़ा कर 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। यह घटना अमेरिका–ईरान संबंधों में निर्णायक मोड़ साबित हुई और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। ईरान–इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, जबकि ईरान ने स्वयं को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता को और गहरा किया। इस दौरान "टैंकर युद्ध" में फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले हुए, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ। 1990 के दशक से अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 2015 में अमेरिका, ईरान और अन्य विश्व शक्तियों (ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के बीच Joint Comprehensive Plan of Action पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अंतर्गत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई। किन्तु 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्म्प ने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया और ईरान पर पुनः कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। जनवरी 2020 में अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमले में ईरानी सैन्य अधिकारी Qasem Soleimani को मार गिराया। यह घटना अमेरिका–ईरान संबंधों में अत्यधिक तनावपूर्ण मोड़ थी। ईरान ने इसके जवाब में इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इस घटना से पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका बढ़ गई और वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार–चढ़ाव देखा गया। हाल के वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, किंतु "प्रॉक्सी युद्ध", साइबर हमले, क्षेत्रीय गठबंधनों और समुद्री टकरावों के माध्यम से तनाव जारी रहा है। ईरान ने लेबनान (हिज़्बुल्लाह), सीरिया और यमन में अपना प्रभाव बढ़ाया,

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब, इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया। अमेरिका–ईरान तनाव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दर्शाता है कि यह संघर्ष केवल वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि ऊर्जा राजनीति, क्षेत्रीय प्रभुत्व, सुरक्षा रणनीति और वैश्विक शक्ति–संतुलन का परिणाम है। इस दीर्घकालिक टकराव ने पश्चिम एशिया को अस्थिर बनाए रखा है, जिसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारत जैसे ऊर्जा–आश्रित देशों पर पड़ता है।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। इसकी लगभग 80: ऊर्जा (विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थ) विदेश से आयात की जाती है। मध्य पूर्व भारत की इन आवश्यकताओं का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। कई वर्षों तक ईरान भारत का तेल और गैस आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत ने पश्चिमी भारत में ईरान से तेल आयात के लिए भुगतान योजनाएँ बनाई, जैसे कि विशेष भुगतान व्यवस्था SWAP और कच्छ–जैबल अली मार्ग, जिससे भारत का तेल प्राप्त करना सस्ता और सुरक्षित था। अमेरिका–ईरान तनाव के कारण तेल के दामों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव देखा गया। तेल की कीमतों की अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है क्योंकि इससे मुद्रा स्फीति, व्यापार घाटा, और ऊर्जा लागत में वृद्धि होती है। भारत ने पिछले दशक में अमेरिका के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाया है कृ जैसे कि QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) और कई रक्षा समझौते। इन साझेदारियों का उद्देश्य चीन को सुदृढ़ संतुलन प्रदान करना है, परंतु अमेरिका–ईरान तनाव में भारत को अपनी प्राथमिकताओं का संतुलन रखने की आवश्यकता है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाए रखे हैं, विशेषकर ऊर्जा, परिवहन और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के क्षेत्र में। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपने हितों के अनुरूप ईरान के साथ सीमित व्यापार जारी रखने की कोशिश की है।

अमेरिका–ईरान तनाव में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाती है। भारत एक भारी तेल आयातक है और ऊपर बढ़ती कीमतें भारतीय रुपये को कमजोर करने में योगदान करती हैं। प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों को ईरान में निवेश और परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह परियोजना जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक परियोजना है, पर कार्यों में देरी हुई। व्यापार प्रतिबंधों ने भारत के कच्चे माल और औद्योगिक उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव डाला है। कुछ भारतीय कंपनियों के लिए ईरानी साझेदारी जोखिमपूर्ण हो गई है क्योंकि अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाता है। भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी होने के बावजूद, भारत को ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखना आवश्यक साबित हुआ है ताकि उसके ऊर्जा हित सुरक्षित रहें। भारत के रणनीतिक हितों में चीन की बढ़ती भूमिका को रोकना शामिल है, और इसके लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हालांकि, ईरान के साथ तनाव ने भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा पर अपनी नीति अधिक जटिल बनाने पर मजबूर किया है। भारत ने अक्सर बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20, SCO आदि में अपनी भूमिका को महत्व दिया है। अमेरिका–ईरान तनाव के कारण भारत ने बहुपक्षीय ढांचे में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है ताकि क्षेत्रीय तनाव को कम करने और कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। भारत को ईरान के अलावा तेल के अन्य स्रोतोंकृजैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और रूसकृपर अधिक भरोसा करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) को बढ़ावा देकर भारत अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम कर सकता है। भारत को अमेरिका तथा ईरान दोनों के साथ संवाद के नए मंच तैयार करने चाहिए, ताकि तनाव के समय संतुलन कायम रह सके। इसके लिए डिप्लोमैटिक बैकलिंक्स, व्यापार समझौते और क्षेत्रीय वार्ता के माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत को क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सुरक्षा गठबंधनों में अधिक सक्रियता से भाग

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

लेना चाहिए, जैसे कि ASEAN, I2U2—ताकि सैन्य और आर्थिक बाधाओं के समय भारत का संतुलन बना रहे। भारत को विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने, व्यापार घाटे को नियंत्रित करने, एवं निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालिक नीतियाँ अपनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत को व्यापार विविधीकरण के माध्यम से नई बाज़ारों की ओर रुख करना चाहिए।

1.1 शोध की आवश्यकता (Need of the Study)– अमेरिका–ईरान तनाव समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक घटना है, जिसका प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करता है। भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और जिसकी ऊर्जा निर्भरता का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है, इस तनाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) के सिद्धांत पर आधारित रही है। एक ओर भारत के अमेरिका के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं; दूसरी ओर ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार तथा मध्य एशिया तक पहुँच का रणनीतिक माध्यम रहा है। इस दोहरे संबंध–संतुलन के कारण भारत को अमेरिका–ईरान तनाव के समय जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में तेल मूल्यों की अस्थिरता, प्रतिबंधों की राजनीति, डॉलर–आधारित वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता, तथा क्षेत्रीय संघर्षों की संभावनाएँ भारत की आर्थिक स्थिरता और विदेशी नीति के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसलिए इस विषय पर गहन, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे यह समझा जा सके कि अमेरिका–ईरान तनाव भारत के आर्थिक और कूटनीतिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा भविष्य में भारत को किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए।

1.2 समस्या का स्वरूप एवं व्याख्या– अमेरिका–ईरान तनाव की समस्या बहुआयामी है। यह केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं, बल्कि एक जटिल भू–राजनीतिक संघर्ष है जिसमें परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभुत्व, ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, प्रतिबंधों की राजनीति और वैश्विक शक्ति–संतुलन जैसे तत्व सम्मिलित हैं। भारत के संदर्भ में समस्या का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट होता है–

ऊर्जा अस्थिरता – ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को सस्ते और स्थिर तेल स्रोतों से वंचित होना पड़ा, जिससे ऊर्जा लागत में वृद्धि हुई।

कूटनीतिक संतुलन का दबाव – अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखते हुए ईरान के साथ संबंधों को संतुलित रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।

व्यापार और निवेश अवरोध – प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों को ईरान में निवेश, बैंकिंग लेन–देन और परियोजनाओं के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम – होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर खतरा भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।

इस प्रकार, समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक और कूटनीतिक भी है। यह भारत की विदेश नीति की व्यवहारिकता और उसकी "रणनीतिक स्वायत्तता" की परीक्षा लेती है।

1.3 अध्ययन का औचित्य (Rationale of the Study)– इस अध्ययन का औचित्य कई स्तरों पर स्पष्ट होता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

- प्रथम, भारत की ऊर्जा सुरक्षा उसके आर्थिक विकास की आधारशिला है। यदि पश्चिम एशिया में अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका सीधा प्रभाव भारत की मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और विकास दर पर पड़ सकता है।
- द्वितीय, भारत की विदेश नीति वर्तमान में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अमेरिका–ईरान तनाव के बीच संतुलन बनाना भारत की कूटनीतिक क्षमता और लचीलापन को परखता है।
- तृतीय, वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था और डॉलर–आधारित वित्तीय प्रणाली में अमेरिका की प्रमुख भूमिका भारत के लिए नीति–निर्माण की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इसलिए यह अध्ययन यह समझने में सहायक होगा कि भारत किस प्रकार वैकल्पिक भुगतान प्रणालियाँ, ऊर्जा विविधीकरण और बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से अपने हितों की रक्षा कर सकता है।
- चतुर्थ, इस विषय पर भारतीय दृष्टिकोण से समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है।

अतः यह शोध भारत–केंद्रित परिप्रेक्ष्य में आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों का समन्वित अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो नीति–निर्माताओं, शोधार्थियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

1.4 अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)– इस शोध का उद्देश्य अमेरिका–ईरान तनाव के संदर्भ में भारत की स्थिति का समग्र विश्लेषण करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1 अमेरिका–ईरान तनाव के ऐतिहासिक और भू–राजनीतिक आयामों का विश्लेषण करना।
2 भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इस तनाव के प्रभाव का अध्ययन करना।
3 भारत के व्यापार, निवेश और आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4 अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाए रखने में भारत की कूटनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण करना।
5 क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्थिरता के संदर्भ में भारत के रणनीतिक हितों की पहचान करना।
6 भविष्य में भारत के लिए संभावित नीति–विकल्पों और रणनीतिक सुझावों को प्रस्तुत करना।

इस प्रकार, यह अध्ययन आर्थिक और कूटनीतिक दोनों आयामों को समाहित करते हुए भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

1.5 शोध–प्रश्न (Research Questions)– इस अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शोध–प्रश्न निर्धारित किए गए हैं–

- अमेरिका–ईरान तनाव के ऐतिहासिक एवं समकालीन आयाम भारत की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
- ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- अमेरिका–ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल मूल्यों में उतार–चढ़ाव का भारत की अर्थव्यवस्था (मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, विनिमय दर) पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- भारत किस प्रकार अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में सफल या असफल रहा है?

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

- क्या ऊर्जा विविधीकरण और बहुपक्षीय कूटनीति भारत के लिए इस तनाव से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकते हैं?
- भविष्य में अमेरिका–ईरान संबंधों की दिशा भारत की सामरिक और आर्थिक नीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?

ये शोध–प्रश्न अध्ययन को विश्लेषणात्मक दिशा प्रदान करते हैं तथा आर्थिक एवं कूटनीतिक दोनों पहलुओं का समग्र परीक्षण सुनिश्चित करते हैं।

1.6 अध्ययन की परिधि एवं सीमाएँ (Scope and Limitations of the Study)–

अध्ययन की परिधि – यह अध्ययन 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से लेकर वर्तमान समय तक के अमेरिका–ईरान संबंधों का विश्लेषण करता है।

अध्ययन विशेष रूप से भारत के आर्थिक (ऊर्जा, व्यापार, निवेश, मुद्रास्फीति) तथा कूटनीतिक (रणनीतिक संतुलन, विदेश नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा) परिणामों पर केंद्रित है।

शोध में पश्चिम एशिया के भू–राजनीतिक संदर्भ, वैश्विक ऊर्जा बाजार तथा बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका का भी परीक्षण किया गया है।

अध्ययन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की अवधारणा के संदर्भ में अमेरिका–ईरान तनाव का मूल्यांकन करता है।

अध्ययन की सीमाएँ– यह शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (सरकारी रिपोर्ट, शोध–पत्र, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आँकड़े) पर आधारित है; प्राथमिक सर्वेक्षण या साक्षात्कार सम्मिलित नहीं हैं।

अध्ययन में केवल भारत के दृष्टिकोण पर केंद्रित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है; अमेरिका और ईरान की आंतरिक राजनीति का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है।

वैश्विक तेल मूल्य और आर्थिक आँकड़े समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए अध्ययन के निष्कर्ष समय–विशिष्ट हो सकते हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा के सभी आयामों (जैसे इज़राइल–ईरान संबंध, सऊदी–ईरान प्रतिस्पर्धा) का विस्तृत विवरण इस शोध की सीमित परिधि के कारण शामिल नहीं किया गया है।

1.7 परिकल्पना (**Hypothesis)-** इस अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं–

प्रमुख परिकल्पना – अमेरिका–ईरान तनाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा यह भारत की विदेश नीति में संतुलन–आधारित रणनीति को अनिवार्य बनाता है।

उप–परिकल्पनाएँ –

1 अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल आयात में कमी करनी पड़ी, जिससे ऊर्जा लागत में वृद्धि हुई।
2 तेल मूल्यों में अस्थिरता भारत के चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है।
3 भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के माध्यम से अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

4 ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण से भारत इस तनाव के आर्थिक प्रभावों को आंशिक रूप से कम कर सकता है।

इन परिकल्पनाओं का परीक्षण उपलब्ध आँकड़ों और विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा।

1.8 शोध प्राविधि (Research Methodology)– इस शोध में गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों विधियों का मिश्रित उपयोग किया गया है।

(अ) शोध का स्वरूप– यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।

(ब) **डेटा के स्रोत–**

1- द्वितीयक स्रोत **(Secondary Sources):**

- भारत सरकार के विदेश मंत्रालय एवं पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्टें
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टें
- विश्व बैंक एवं IMF के आँकड़े
- शोध–पत्र, जर्नल लेख, पुस्तकें
- समाचार विश्लेषण और नीति–पत्र

2. आर्थिक आँकड़े–

- तेल आयात के आँकड़े
- व्यापार घाटा
- मुद्रास्फीति दर
- विनिमय दर परिवर्तन

(स) विश्लेषण की पद्धति

- तुलनात्मक विश्लेषण
- प्रवृत्ति विश्लेषण
- नीति–विश्लेषण
- ऐतिहासिक पद्धति

(द) सैद्धांतिक आधार– अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवाद, उदारवाद और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांतों का संदर्भ लिया गया है, ताकि भारत की विदेश नीति को सैद्धांतिक रूप से समझा जा सके।

1.9 साहित्य समीक्षा (Review of Literature)– अमेरिका–ईरान संबंधों, पश्चिम एशिया की भू–राजनीति तथा भारत की ऊर्जा और कूटनीतिक नीति पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है। विभिन्न विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा नीति–विश्लेषकों ने इस विषय के अलग–अलग आयामों पर अध्ययन किया है।

(1) अमेरिका–ईरान संबंधों पर साहित्य– अमेरिका–ईरान संबंधों के ऐतिहासिक विश्लेषण में म्तअंदक ।इतींउपंद और त्ंल जंमली जैसे विद्वानों ने 1953 के तख्तापलट, 1979 की इस्लामी क्रांति और उसके बाद के वैचारिक टकराव का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक अविश्वास और क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। परमाणु समझौते पर आधारित साहित्य में 2015 के Joint Comprehensive Plan of Action को एक कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा गया, किंतु 2018 में अमेरिका

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

के हटने के बाद पुनः तनाव बढ़ने पर अनेक शोधों ने प्रतिबंधों की राजनीति और वैश्विक शक्ति–संतुलन का विश्लेषण किया है।

(2) ऊर्जा सुरक्षा और भारत– भारत की ऊर्जा नीति पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और विश्व बैंक की रिपोर्टों में यह रेखांकित किया गया है कि भारत की लगभग 80 प्रतिशत तेल आवश्यकता आयात पर निर्भर है। शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता सीधे भारत की मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटे और विकास दर को प्रभावित करती है। भारतीय विद्वानों जैसे सी. राजा मोहन, हर्ष पंत और श्याम सरन ने भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" की अवधारणा के संदर्भ में अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है।

(3) प्रतिबंधों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अध्ययन– आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव पर कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि प्रतिबंध न केवल लक्षित देश बल्कि उससे जुड़े व्यापारिक साझेदारों को भी प्रभावित करते हैं। ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को वैकल्पिक तेल स्रोतों की ओर रुख करना पड़ा, जिससे परिवहन लागत और भुगतान व्यवस्था में परिवर्तन हुआ।

(4) साहित्य में अंतराल (Research Gap)– हालांकि अमेरिका–ईरान संबंधों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर अलग–अलग अध्ययन उपलब्ध हैं, किंतु भारत–केंद्रित दृष्टिकोण से आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों का समन्वित विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। यह शोध इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

1.10 डेटा विश्लेषण (Data Analysis)– इस अध्ययन में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं–

(1) तेल आयात में परिवर्तन– अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में उल्लेखनीय कमी की। 2017–18 में ईरान भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता था, किंतु 2019 के बाद यह आयात लगभग शून्य के निकट पहुँच गया। इसके स्थान पर भारत ने सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और रूस से आयात बढ़ाया।

(2) तेल मूल्य और मुद्रास्फीति– अमेरिका–ईरान तनाव के दौरान वैश्विक तेल कीमतों में उतार–चढ़ाव देखा गया। जब भी तनाव बढ़ाकृजैसे 2019 में टैंकर हमलों या 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद–कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। इससे भारत में पेट्रोल–डीजल की कीमतें बढ़ीं और मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ा।

(3) चालू खाता घाटा और विनिमय दर– तेल आयात महँगा होने से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ा और रुपये पर दबाव पड़ा। डॉलर–आधारित भुगतान प्रणाली में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को विशेष भुगतान व्यवस्था (जैसे रुपये–रियाल तंत्र) अपनानी पड़ी।

(4) कूटनीतिक गतिविधियाँ– भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संवाद जारी रखा। एक ओर अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा, वहीं दूसरी ओर भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना को जारी रखने का प्रयास किया।

डेटा से यह स्पष्ट है कि आर्थिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर भारत को समायोजन करना पड़ा।

1.11 चर्चा (Discussion)–

डेटा और साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका–ईरान तनाव ने भारत को "संतुलन–नीति" अपनाने के लिए बाध्य किया।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

पहला, ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। ईरान से आयात बंद होने पर भारत को वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी पड़ी, जिससे लागत और रणनीतिक निर्भरता में बदलाव आया।

दूसरा, कूटनीतिक दृष्टि से भारत ने किसी भी पक्ष का खुला समर्थन करने से परहेज किया और बहुपक्षीय मंचों पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की।

तीसरा, यह तनाव भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है। अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग और ईरान के साथ क्षेत्रीय संपर्ककृदोनों को बनाए रखना आसान नहीं रहा।

चौथा, यह स्थिति भारत के लिए अवसर भी प्रस्तुत करती हैकृऊर्जा विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और बहुपक्षीय कूटनीति को सुदृढ़ करने का।

इस प्रकार, चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत ने व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, किंतु आर्थिक दबावों को पूर्णतः टालना संभव नहीं था।

1.12 परिणाम (Findings)– अध्ययन के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम सामने आते हैं–

- अमेरिका–ईरान तनाव के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई और तेल आयात नीति में बदलाव करना पड़ा।
- तेल कीमतों में अस्थिरता से भारत की मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत–ईरान व्यापार और निवेश परियोजनाओं को सीमित किया।
- भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के तहत संतुलित कूटनीति अपनाई।
- ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देने से भारत ने आंशिक रूप से जोखिम को कम किया।
- भविष्य में पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अतः यह स्पष्ट है कि अमेरिका–ईरान तनाव भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण किंतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिसने भारत को अपनी आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों में अधिक लचीलापन और संतुलन अपनाने के लिए प्रेरित किया।

नीति अनुशंसाएँ (Policy Recommendations)– अमेरिका ईरान तनाव के संदर्भ में भारत के आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की जाती हैं–

1 भारत को ईरान या किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए सऊदी अरब, इराक, यूएई, रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से तेल आयात का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे आपूर्ति जोखिम कम होगा।

2 भारत को अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को और बढ़ाना चाहिए, ताकि वैश्विक संकट या आपूर्ति बाधा की स्थिति में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

3 सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाकर भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इससे पश्चिम एशिया पर निर्भरता घटेगी।

4 अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को रुपये–आधारित व्यापार प्रणाली तथा बहुपक्षीय भुगतान तंत्र को मजबूत करना चाहिए, जिससे डॉलर–निर्भरता कम हो सके।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

5 भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के बजाय शांतिपूर्ण समाधान और वार्ता का समर्थन करना भारत के दीर्घकालिक हित में होगा।

6 ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की मध्य एशिया तक पहुँच का रणनीतिक माध्यम है। इसे प्रतिबंधों के बावजूद प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

7 भारत को संयुक्त राष्ट्र, G20, SCO जैसे मंचों पर क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों को उठाकर कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देना चाहिए।

8 होर्मुज़ जलडमरूमध्य और हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग और निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए, ताकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति मार्ग सुरक्षित रह सके।

9 तेल उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध कर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे अचानक मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सके।

10 भारत को तेल मूल्य अस्थिरता से निपटने के लिए वित्तीय हेजिंग, विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ीकरण और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए।

11 भारत को अपनी विदेश नीति में "रणनीतिक स्वायत्तता" को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वह बदलती वैश्विक परिस्थितियों में स्वतंत्र और संतुलित निर्णय ले सके।

इन अनुशंसाओं का उद्देश्य भारत को अमेरिका–ईरान तनाव से उत्पन्न आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन करने में सक्षम बनाना है। संतुलित विदेश नीति, ऊर्जा विविधीकरण, और बहुपक्षीय कूटनीति ही भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion)– अमेरिका–ईरान तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में एक जटिल चुनौती है। भारत, जो ऊर्जा–आश्रित और वैश्विक पार्टनरशिप में वृद्धि की ओर अग्रसर है, इस संघर्ष के प्रभावों से सीधे प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतों में अस्थिरता, व्यापार घाटा, सीमित निवेश, और कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ भारत को नई रणनीतियाँ अपनाने पर मजबूर कर रही हैं। इसके बावजूद, भारत के लिए अवसर भी हैं, जैसे कि ऊर्जा विविधीकरण, रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार, और बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभाना। भारत का संतुलन–भरी और दूरदर्शी विदेश नीति, दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएँ, और बढ़ती वैश्विक भागीदारी ही भविष्य में इस तनाव के प्रभावों को न्यूनतम कर सकती हैं।

संदर्भ सूची –

01. Abrahamian, E. (2008). *A History of Modern Iran*. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521528917.
02. Takeyh, R. (2009). *Guardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs*. Oxford University Press. ISBN: 978-0195398083.
03. Parsi, T. (2017). *Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy*. Yale University Press. ISBN: 978-0300218169.
04. Kerr, P. K. (2022). *Iran's Nuclear Program: Status*. Congressional Research Service Report.
05. International Energy Agency (IEA). (2023). *World Energy Outlook 2023*. Paris: IEA Publications.
06. Ministry of External Affairs, Government of India. (2022). *Annual Report 2021–22*. New Delhi: MEA Publications.
07. Pant, H. V. (2019). *Indian Foreign Policy: An Overview*. Manchester University Press. ISBN: 978-1526135052.

08. Mohan, C. R. (2003). *Crossing the Rubicon: The Shaping of India's New Foreign Policy*. Viking. ISBN: 978-0670048151.
09. Tellis, A. J. (2016). *India as a Leading Power*. Carnegie Endowment for International Peace. ISBN: 978-0870033049.
10. World Bank. (2023). *Global Economic Prospects*. Washington, DC: World Bank Publications.
11. International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook*. Washington, DC: IMF Publications.
12. Cordesman, A. H. (2020). *The Gulf and the Search for Strategic Stability*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
13. Saran, S. (2017). *How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century*. Juggernaut Books. ISBN: 978-9386228093.